

उत्तराखण्ड शासन
आवास अनुभाग
संख्या: 878 / V / आ०-२२०७-२६(न०वि०) / २००१
देहरादून: दिनांक: ३० अप्रैल, २००७

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या: 3404 / V / आ०-२२०६-२६(न०वि०) / २००१, दिनांक: ७-१२-२००६ को अतिक्रमित करते हुए उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य विभागन अधिनियम, 1958 की धारा-15 (क)(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के अन्तर्गत आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के समक्ष प्रस्तुत वाद/अपील/निगरानी एवं विधिक मामलों में सुनवाई हेतु डा०एम०सी०जोशी, अपर सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अधिकृत किया जाता है। साथ ही उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 (यथाराशोधित) की धारा 41 (3), उत्तर प्रदेश विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 (यथा संशोधित) की धारा 38(3) तथा अन्य विभिन्न विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत शासन को प्रस्तुत अपील/निगरानी एवं विधिक मामलों में सुनवाई हेतु भी डा०एम०सी०जोशी को राज्य सरकार की ओर से निर्वाचित करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

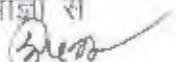
2— श्री जोशी को निर्देशित किया जाता है कि ये राज्य सरकार में आवास विभाग के समक्ष प्रस्तुत विभिन्न विधिक प्रकरणों में सुनवाई के पश्चात यथाआवश्यकता रथगनादेश एवं अंतिम आदेश पारित करें।

(शनुधन सिंह)
सचिव

संख्या: 878(२) / V / आ०-२२०७-२६(न०वि०) / २००१ / तदिनांक

प्रतिलिपि गिम्नलिखित को रूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यगाही हेतु प्रेपित—

- 1— समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 2— उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण, देहरादून / नैनीताल।
- 3— अपर सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4— सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, नैनीताल / देहरादून / गंगोत्री।
- 5— वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड।
- 6— संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रुडकी, हरिद्वार को इस आशय से प्रेपित कि ये उत्तराखण्ड के सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करने का काम करें।
- 7— निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड राजिकालय परिसर, देहरादून।
- 8— गार्ड बुक।
- 9— डा० स्म. स्ट्रौ. जोशी, अपर सचिव, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से

(एस०क०प०त्ता)
अनुसंचित